साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

वर्ष : 10, अंक : 47 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 25 जून 2025 से 1 जुलाई 2025 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

एलएनजी से होने वाले उत्सर्जन में 60 फीसदी तक कटौती संभव, आईईए ने बताया रास्ता

मुंबई अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने अपनी नई रिपोर्ट में जानकारी दी है कि मौजूदा तकनीकों की मदद से तरल प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी की आपूर्ति श्रृंखला से होने वाले ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में 60 फीसदी से अधिक की कटौती की जा सकती है। गौरतलब है कि ताजा आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट में एलएनजी की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से होने वाले उत्सर्जन का आकलन पेश किया गया है और इसे कम करने के अहम उपाय बताए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एलएनजी की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से हर साल करीब 35 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। इसमें से करीब 70 फीसदी उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, जबकि बाकी 30 फीसदी मीथेन होती है, जो बिना जले ही वातावरण में पहुंच रही है।

रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि जब दुनियाभर में एलएनजी सप्लाई की जाती है, तो हर मेगाजूल ऊर्जा पर औसतन 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जन होता है। वहीं, सामान्य प्राकृतिक गैस से होने वाले यह उत्सर्जन औसतन 12 ग्राम होता है। हालांकि, यह उत्सर्जन अलग-अलग देशों और सप्लाई के रास्तों पर निर्भर करता है। आईईए के मुताबिक 2024 में

जितनी भी एलएनजी खपत हुई, उससे जुड़े उत्सर्जन को यदि जोड़ा जाए तो 99 फीसदी से ज्यादा एलएनजी से होने वाला कुल उत्सर्जन कोयले से कम था। औसतन, एलएनजी से कोयले की तुलना में करीब 25% कम उत्सर्जन होता है। हालांकि, रिपोर्ट यह भी कहती है कि एलएनजी को सिर्फ कोयले से बेहतर बताकर उसकी पर्यावरणीय छवि नहीं सुधारी जा सकती, क्योंकि इसकी सप्लाई चेन से होने वाले उत्सर्जन को कम करने की अभी भी बड़ी संभावनाएं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा तकनीकों की मदद से एलएनजी सप्लाई से होने वाले उत्सर्जन में 60 फीसदी से ज्यादा की कटौती की जा सकती है, और इनमें से कई उपाय तो कम खर्च पर भी किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए सिर्फ मीथेन के रिसाव को रोककर ही हर साल करीब 9 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोका जा सकता है, जो एलएनजी से होने वाले कुल उत्सर्जन का करीब 25 फीसदी है। इसमें से आधी कटौती तो बिना किसी अतिरिक्त खर्च के संभव है। इसके अलावा, एलएनजी प्लांट और गैस सप्लाई करने वाले क्षेत्रों में गैस जलाने (फ्लेरिंग) को कम करके भी हर साल 50 लाख टन उत्सर्जन घटाया जा सकता है। रिपोर्ट में कुछ और असरदार और किफायती उपाय भी बताए गए हैं, जिनसे एलएनजी से होने वाला उत्सर्जन काफी हद तक घटाया जा सकता है। इनमें सप्लाई चेन की प्रक्रिया को ज्यादा ऊर्जा-दक्ष बनाना और तरलीकरण संयंत्रों में मौजूद प्राकृतिक कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने के लिए कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण तकनीक का इस्तेमाल करना शामिल है। हालांकि शुरुआत में इसकी लागत ज्यादा हो सकती है, लेकिन अगर गैस उत्पादन इकाइयों और एलएनजी टर्मिनलों को कम उत्सर्जन वाली बिजली से चलाया जाए, तो उत्सर्जन में करीब 11 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर की और कमी हो सकती है।

पानी से बनेगी ग्रीन हाइड्रोजन, भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया अगली पीढ़ी का उपकरण

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा अगली पीढ़ी की डिवाइस तैयार किया है जो सिर्फ सौर ऊर्जा से पानी के अणुओं को तोड़कर ग्रीन हाइड्रोजन में बदल सकता है। यह डिवाइस बेहद किफायती होने के साथ-साथ, स्केलेबल है यानी इसे बड़े पैमाने पर भी बनाया जा सकता है। इसकी एक बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए महंगे संसाधनों या जीवाश्म ईंधन की जरूरत नहीं है।

इस उपकरण का विकास बेंगलुरु के सेंटर फार नैनो एंड साफ्ट मैटर साइंसेज (सीईएनएस) के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। बता दें कि सीईएनएस विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। गौरतलब है कि ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इससे न केवल फैक्ट्रियों, उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। साथ ही वाहनों को चलाने और अक्षय ऊर्जा को स्टोर करने में भी मदद मिलती है। लेकिन अब तक इसे सस्ते और बड़े स्तर पर बनाना बड़ी चुनौती थी। डॉक्टर आशुतोष के सिंह के नेतृत्व में शोधकर्ताओं के दल ने एक ऐसा सिलिकॉन आधारित फोटोएनोड तैयार किया है जो पानी के अणुओं को सोलर एनर्जी की मदद से तोड़कर हाइड्रोजन में बदल सकता है। इस तरह से उपकरण की जीवाश्म ईंधन या महंगे संसाधनों पर निर्भरता नहीं रहती। डॉक्टर अशुतोष के सिंह के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने अत्याधुनिक सिलिकॉन आधारित फोटोएनोड तैयार किया है, जो पानी को सोलर एनर्जी की मदद से हाइड्रोजन में बदलता है। इसके लिए उन्होंने एन-आई-पी हेटेरोजंक्शन नाम की खास तकनीक का इस्तेमाल किया जिसमें सेमीकंडक्टर की तीन परतें होती हैं। इन परतों में स्टैक्ड एन-टाइप टीआईओ2, आंतरिक (अनडॉप्ड) एसआई, और पी-टाइप एनआईओ सेमीकंडक्टर शामिल हैं। इन परतों को मैग्नेट्रॉन स्पटरिंग नाम की तकनीक से जमा किया गया, जो औद्योगिक स्तर पर इस्तेमाल के लिए उपयुक्त और सटीक है। इससे सूरज की रोशनी अच्छे से अवशोषित होती है, चार्ज ट्रांसपोर्ट तेज होता है और ऊर्जा की बर्बादी कम से कम होती है। वैज्ञानिकों द्वारा बनाए इस उपकरण की सफलता केवल शोध पत्र तक सीमित नहीं है, यह उपकरण जमीनी स्तर पर भी असरदार साबित हुआ है। इस डिवाइस ने 600 एमवी का सरफेस फोटोवोल्टेज और मात्र 0.11 वीआरएचई का ऑनसेट पोटेंशियल हासिल किया, जो इसे सूरज की रोशनी से हाइड्रोजन बनाने में बेहद प्रभावी बनाता है। 2050 तक भारत में हाइड्रोजन की मांग और खपत पांच गुना तक बढ़ने की उम्मीद है;

इतना ही नहीं, इसने क्षारीय परिस्थितियों में 10 घंटे तक लगातार काम किया और प्रदर्शन में केवल 4 फीसदी की गिरावट आई — जो कि एसआई-आधारित फोटोइलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम के लिए दुर्लभ है। सबसे खास बात यह है कि यह तकनीक न सिर्फ असरदार है,

बल्कि सस्ती, टिकाऊ और बड़े स्तर पर भी कारगर है। रिसर्च टीम ने 25 सेंटीमीटर के वर्गाकार बड़े फोटोएनोड से भी बेहतरीन परिणाम हासिल किए। डॉक्टर सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी देते हुए कहा, स्मार्ट मटेरियल का चयन कर और उन्हें सही तरीके से जोड़कर हमने एक ऐसा उपकरण बनाया है जो न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन करता है, बल्कि बड़े स्तर पर भी बनाया सकता है। यह हमें सौर ऊर्जा से हाइड्रोजन बनाने के सस्ते और व्यावसायिक समाधान के एक कदम और करीब ले जाता है। इस उपकरण से जुड़े अध्ययन के नतीजे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा प्रकाशित जर्नल ऑफ मैटेरियल्स केमिस्ट्री ए में प्रकाशित हुए हैं।

जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही हमारा लक्ष्य –राज्यमंत्री श्रीमती गौर

गोविंदपुरा क्षेत्र में 70 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया भूमि-पूजन

भोपाल पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर ने कहा भारतीय संस्कृति में मान्यता है कि विधि-विधान से पूजा करने से कार्य में कोई बाधा नहीं आती। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ जनता के सेवक हैं। जनप्रतिनिधि एक जनसेवक होता है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही उसका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जनता का साथ और विकास का संकल्प - यही मेरी प्रतिबद्धता राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने सोमवार को गोविंदपुरा क्षेत्र में 70 लाख रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन किया।

राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने रजत विहार कॉलोनी में 5 लाख रुपए की लागत से पेविंग ब्लॉक निर्माण कार्य और 7 लाख रुपए की लागत से सी.सी. सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन कर विकास कार्यों का शुभारंभ किया। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन राष्ट्रसेवा की अमर प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में लगभग 4 लाख रुपए की लागत पेवर ब्लॉक कार्य का निर्माण कराया जाएगा। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि गोविन्दपुरा क्षेत्र के वार्ड 54 के दुर्गा नगर मंदिर परिसर में पेवर ब्लॉक और मंदिर की छत डलने के निर्माण कार्य का भूमिपूजन क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में किया। राज्यमंत्री श्रीमती गौर ने कहा कि यह कार्य श्रद्धालुओं की सुविधा एवं परिसर के सौंदर्यीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने वार्ड 54 के स्टर्लिंग केसेल्स में 3 लाख रुपए की लागत से पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य, कुंजन नगर में 22 लाख रुपये लागत के नाली निर्माण कार्य एवं पार्क निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया। बागसेवनिया में 24 लाख लागत के कबीरपंथी समाज भवन उन्नयन कार्य, पार्क निर्माण एवं सड़क निर्माण के कार्यों का भूमि-पूजन किया। इस दौरान पार्षद श्री जितेन्द्र शुक्ला, श्रीमती शीला पाटीदार, श्रीमती अर्चना परमार, श्रीमती मोनिका ठाकुर, श्री प्रताप वारे, श्री रामबाबू पाटीदार, श्री धर्मेंद्र पाटीदार, श्री प्रदीप पाठक, श्री अनिल मालवीय सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे।

विधायकों को अब डिजिटली रिकॉर्ड देने की तैयारी

भोपाल (एजेंसी)मानसून सत्र में सदन का नजारा बदला-बदला नजर आएगा। हर विधायक की टेबल पर टैबलेट होगा। इस टैबलेट में सदन संबंधी सभी जानकारी उपलब्ध होगी। सिंगल क्लिक पर उन्हें यह जानकारी मिल सकेगी। यहां तक प्रश्नोत्तरी, राज्य का बजट, विभागीय प्रतिवेदन सहित अन्य सामग्री डिजिटली फार्मेट में होगी। ऐसे में विधायको को अपने साथ दस्तावेज लाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए विधानसभा सचिवालय ने तैयारी कर ली है।

विधानसभा सचिवालय ने सदन के काम-काज को हाइटेक तरीके से किए के लिए पूरी जिमेदारी एनआइसी को दी है। एनआईसी को बता दिया गया है कि मानसून सत्र तक सिस्टम तैयार करना है। इसी को ध्यान में रखकर तैयारी की जा रही है। विधानसभा प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह बताते हैं कि प्रयास यही है कि मानसून सत्र के पहले तक पूरी व्यवस्थाएं हो जाएं। यदि सिस्टम ऑनलाइन हो गया तो विधायकों को सदन संबंधी सामग्री भी डिजिटल फार्मेट में दी जाना शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अभी फोकस विधायकों के प्रशिक्षण पर है। शुरुआत में सभी विधायकों को मौजूदा व्यवस्था के तहत हार्डकॉपी दी जाएगी। सॉट कॉपी भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। धीरे-धीरेपूरी व्यवस्था ही ऑनलाइन करदी जाएगी। विधानसभा सचिवालय और मंत्रालय के बीच ऑनलाइन काम-काज पहले से है। इसके लिए विशेष सॉटवेयर बनाया गया है। विधायकों द्वारा पूछे गए लिखित सवाल इसी के माध्यम से सरकार के संबंधित विभागों को विधानसभा सचिवालय भेजता है और उनके जवाब भी इसी माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। अन्य जानकारियां भी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से आती है। विधायक भी ऑनलाइनसवाल भेजते हैं। डिजिटल सिग्नेचर से ई-मेल भी मान्य विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों के ई-मेल एड्रेस तैयार कराए हैं। सभी के डिजिटल सिग्नेचर भी सचिवालय के पास हैं। ऑनलाइन काम-काज में इन डिजिटल सिग्नेचर को मान्य किया जाता है। अब ऑनलाइन वर्किंग को और विस्तार दिया जा रहा है।

डेटा सुरक्षा बढ़ाने BSNL सेवा उपयोग करे सरकार

इंदौर दूरसंचार विभाग ने डेटा सुरक्षा और कैबिनेट के फैसले का हवाला देते हुए राज्य सरकारों से दूरसंचार सेवाओं के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। यह निर्देश दूरसंचार विभाग ने एक पत्र के माध्यम से राज्य सरकारों को दिया है। दूरसंचार सलाहकार समिति के वरिष्ठ सदस्य रामस्वरूप मूंदड़ा ने बताया, दूरसंचार विभाग ने डेटा सुरक्षा आवश्यकताओं का हवाला देते हुए पत्र लिखा है। दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने पत्र से इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज्ड लाइन आवश्यकताओं के लिए सरकार के सभी विभागों, एजेंसियों, पीएसयू द्वारा बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाओं के उपयोग करने की बात कही।

स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता, सेवा गुणवत्ता और जनविश्वास का समन्वय आवश्यक –उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

समस्त स्वास्थ्य संस्थानों को मानक अनुरूप बनाने के लिये करें सघन प्रयास

जिला चिकित्सालय सिवनी और देवास कायाकल्प में प्रथम, एनक्यूएएस मापदंड में दतिया शीर्ष पर

भोपाल उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि स्वास्थ्य संस्थानों में उपचार के साथ-साथ स्वच्छता और साफ-सफाई भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं केवल दवा और इलाज तक सीमित नहीं हैं, बल्कि अस्पताल परिसर का वातावरण, संक्रमण नियंत्रण, स्वच्छता और मरीजों को मिलने वाली संपूर्ण देखरेख भी उतनी ही आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं ने कायाकल्प, एन.क्यू.ए.एस., मुस्कान और लक्ष्य जैसे कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर यह प्रमाणित किया है कि हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल एवं लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने स्वर्ण जयंती सभागार नारोन्हा प्रशासनिक अकादमी भोपाल में वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 के कायाकल्प, एनक्यूएएस, मुस्कान एवं लक्ष्य कार्यक्रमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वास्थ्य संस्थाओं को सम्मानित किया।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह उपलब्धियाँ प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की ओर बढ़ते कदम हैं। उन्होंने कहा कि यह सराहनीय है कि बड़ी संख्या में संस्थान इन मापदंडों पर खरे उतर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि शेष संस्थाओं को भी इन मानकों के अनुरूप विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के संपूर्ण सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में 10 हज़ार करोड़ की लागत के स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास के कार्य प्रगति पर हैं। साथ ही, स्वास्थ्य विभाग में 3 हज़ार चिकित्सकों सहित कुल 35 हज़ार पदों पर नियुक्तियाँ की जा रही हैं, जिससे मैनपावर की कमी दूर होगी और सेवा प्रदाय की गुणवत्ता बेहतर होगी। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के सभी 12,000 से अधिक स्वास्थ्य संस्थान कायाकल्प, एन.क्यू.ए.एस., लक्ष्य और मुस्कान जैसे मानकों पर खरे उतरें, इसके लिए केवल बजट और संसाधनों की नहीं, बल्कि सतत मॉनिटरिंग, संस्थागत प्रशिक्षण और कर्मचारियों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। हर संस्थान को सशक्त और उत्तरदायी बनाकर प्रदेश के हर क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कराना हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 'स्वस्थ भारत' के लक्ष्य की दिशा में मध्यप्रदेश लगातार उल्लेखनीय उपलब्धियाँ अर्जित कर रहा है। कायाकल्प अवार्ड जैसे कार्यक्रम इन प्रयासों को प्रोत्साहित करने वाले महत्वपूर्ण साधन हैं। उन्होंने सभी स्वास्थ्यकर्मियों की प्रतिबद्धता और सेवा भावना की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता का आधार वही लोग हैं जो अस्पतालों में दिन-रात जनसेवा के लिए समर्पित रहते हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में मातृ मृत्यु दर वर्ष 2020 के 175 के मुकाबले घटकर 159 पर आ गई है, जो एक सकारात्मक संकेत है। परंतु उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सुधार पर्याप्त नहीं है और अभी हमें बहुत आगे जाना है। इस दिशा में उन्होंने गर्भवती माताओं के शत-प्रतिशत पंजीयन, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की समय पर पहचान और उनके समुचित उपचार के लिए ठोस, योजनाबद्ध और ज़मीनी स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकी सेवाओं को भी सशक्त बना रही है ताकि दूरस्थ क्षेत्रों में भी विशेषज्ञों की राय और इलाज की सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि कायाकल्प अभियान की शुरुआत वर्ष 2015-16 में हुई थी, जब केवल 9 संस्थाएं मापदंडों पर खरी उतर सकीं थीं, वहीं वर्ष 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 675 स्वास्थ्य संस्थाओं तक पहुँच चुकी है। इससे स्पष्ट है कि राज्य की प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है। यह परिवर्तन मात्र संख्या नहीं, बल्कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और जनविश्वास का प्रतीक है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पूर्ण समर्पण से स्वास्थ्य विभाग का अमला कार्य करें। सशक्त स्वास्थ्य से ही हम विकसित भारत और विकसित मध्यप्रदेश का स्वप्न पूर्ण कर पाएंगे। उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य संस्थानों और चिकित्सकीय टीम को बधाई दी। उल्लेखनीय है कि कायाकल्प, एन.क्यू.ए.एस., लक्ष्य एवं मुस्कान पुरस्कारों का उद्देश्य प्रदेश की शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण, सेवा गुणवत्ता एवं मातृ-शिशु देखभाल में उत्कृष्ट मानक सुनिश्चित करना है। इन पुरस्कारों की शुरुआत भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने हेतु की गई, जिनके तहत संस्थाओं का मूल्यांकन निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया जाता है। कायाकल्प अवार्ड स्वच्छता, ईको-फ्रेंडली उपायों, अपशिष्ट प्रबंधन और अस्पताल रखरखाव के लिए प्रदान किया जाता है। एन.क्यू.ए.एस. अवार्ड सेवा की गुणवत्ता, रोगी सुरक्षा और क्लिनिकल प्रोटोकॉल के पालन के आधार पर दिया जाता है। लक्ष्य अवार्ड सुरक्षित प्रसव सेवाओं के लिए और मुस्कान अवार्ड बाल रोग सेवाओं की उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों से स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार को बढ़ावा मिलता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार परिलक्षित हुआ है। वर्ष 2023-24 के अंतर्गत महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय देवास को जिला चिकित्सालय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार (?15 लाख), सिविल अस्पताल हजीरा (ग्वालियर) को सीएचसी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार (?10 लाख), पीएचसी अमलाहा (सीहोर) को सह-विजेता के रूप में (?1 लाख), तथा मक्सी (शाजापुर) और संजयनगर (जबलपुर) स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को संयुक्त रूप से प्रथम पुरस्कार (?2 लाख) से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024-25 के अंतर्गत इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय सिवनी को जिला चिकित्सालय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार (15 लाख), सिविल अस्पताल पाटन (जबलपुर) को सीएचसी श्रेणी में प्रथम पुरस्कार (10 लाख), और पीएचसी पिटोल (झाबुआ) को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र श्रेणी में प्रथम पुरस्कार (?2 लाख) प्रदान किया गया। वर्ष 2023-24 में इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय, सिवनी को प्रथम रनर-अप (87.19%) तथा सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण-अनुकूल जिला चिकित्सालय (95.71%) श्रेणी में 10 लाख एवं 5 लाख का पुरस्कार प्रदान किया गया। सेठ गोविंद दास जिला चिकित्सालय, जबलपुर को द्वितीय रनर-अप (84.35%) के रूप में 5 लाख की राशि से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष सीएचसी दौराहा, सीहोर को प्रथम रनर-अप (93.86%) के रूप में 5 लाख तथा सिविल अस्पताल हजीरा, ग्वालियर को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण-अनुकूल सीएचसी (92.86%) श्रेणी में 2.5 लाख का पुरस्कार मिला। वर्ष 2024-25 में जिला चिकित्सालय बुरहानपुर को प्रथम रनर-अप (94.61%) श्रेणी में 10 लाख तथा जिला चिकित्सालय भिंड को द्वितीय रनर-अप (90.76%) और सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण-अनुकूल जिला चिकित्सालय (95%) श्रेणियों में 5 लाख- 5 लाख के संयुक्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार सीएचसी मानपुर, इंदौर को प्रथम रनर-अप (91.07%) के रूप में 5 लाख तथा सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण-अनुकूल सीएचसी (96%) के लिए 2.5 लाख का पुरस्कार प्राप्त हुआ।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में जल क्रांति

सिंचाई का रकबा बढ़ने के साथ ग्रामीणों की बढ़ेगी आय

प्रदेश में पहली बार एआई, सिपरी और प्लानर सॉफ्टवेयर जैसी तकनीक का उपयोग

2334.55 करोड़ रुपये की लागत से मनरेगा से हो रहा जल संरचनाओं का निर्माण कार्य

भोपाल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं को मजबूती देने के साथ ही प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण की दिशा में देश भर में चलाए जा रहे अभियान को मध्यप्रदेश सरकार मिशन के रूप में चला रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जल क्रांति हो रही है। इस क्रांति के अंतर्गत जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा खेत तालाब, अमृत सरोवर, डगवेल रिचार्ज बनाए जा रहे हैं। इन कार्यों से प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, साथ ही भू-जल स्तर में भी सुधार होगा और ग्रामीण आजीविका को भी बढ़ावा मिलेगा।

बारिश के पानी का संचयन बड़े स्तर पर किया जा सके, इसके लिए मनरेगा परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू होने के तीन माह पहले जनवरी से ही तैयारी प्रारंभ कर दी गई थी। इसके लिए परिषद द्वारा प्लानर सॉफ्टवेयर तैयार कराया गया जिसमें कम से कम प्रविष्टि करते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर योजना को अंतिम रूप दिया जा सके। जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत लिए जाने वाले नवीन कार्यों को इस प्लान में शामिल किया गया। इसके अलावा पिछले वर्ष के प्रगतिरत कार्यों को पूरा करने के लिए उन कार्यों को भी कार्ययोजना में जोड़ा गया गया। प्लानर सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य था मनरेगा के उद्देश्यों एवं प्रावधानों का पालन कराते हुए कार्ययोजना को आसान तरीके से बनाया जाना। परिषद द्वारा साफ्टवेयर के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर कराए जाने वाले कार्यों की वार्षिक कार्ययोजना तैयार कराई। खास बात यह रही कि मध्यप्रदेश इस तरह का नवाचार करने वाला देश का पहला राज्य भी है। तकनीक के साथ बारिश के पानी को संचय किया जा सके, साथ ही नई जल संरचनाओं के निर्माण के लिए स्थल चयन में भी आसानी हो, इसके लिए मनरेगा परिषद द्वारा सिपरी सॉफ्टवेयर बनाया गया। यह सॉफ्टवेयर

(सॉफ्टवेयर फॉर आइडेंटीफिकेशन एंड प्लानिंग ऑफ रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर) एक उन्त तकनीक का साफ्टवेयर है, जिसे महात्मा गांधी नरेगा, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल द्वारा स्वश्रेष्ठ और इसरो के सहयोग से तैयार कराया गया है। इस साफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण के लिए उपयुक्त स्थलों की सटीक पहचान कर गुणवत्तापूर्ण संरचनाओं का निर्माण सुनिश्चित करना है। इसके अलावा यह भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित वैज्ञानिक पद्धतियों से जल सरंचना स्थलों के चयन को अधिक सटीक बनाता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रदेश में बड़ी संख्या में नई जल संरचनाओं जैसे खेत तालाब, अमृत सरोवर और डगवेल रिचार्ज के निर्माण के लिए स्थल का चयन किया गया। प्रदेश में किए गए इस तरह के प्रयोग को देखने के लिए बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र से अधिकारियों का दल भी आ चुका है। जल गंगा संवर्धन अभियान में मनरेगा योजना के तहत होने वाले कार्यों की पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही नियमित तौर पर इसकी मॉनिटरिंग भी की जा सके, इसके लिए परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान का डैशबोर्ड बनाया गया। डैशबोर्ड के माध्यम के प्रत्येक जिले में क्या-क्या कार्य हो रहे हैं उसकी राशि कितनी है। यह सब आसानी से देखा जा सकता है। साथ ही कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रत्येक सप्ताह की प्रगति रिपोर्ट भी कलेक्टर को उपलब्ध कराई जा रही है। जल गंगा संवर्धन अभियान के लिए बनाए गए डैशबोर्ड को नियमित 1 लाख 27 हजार से अधिक लोग देख भी रहे हैं।

प्रदेश में बारिश के पानी का संचयन करने और पुराने जल स्त्रोतों को नया जीवन देने के लिए 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत हुई थी। इसका समापन 30 जून को खंडवा में होगा। 90 दिन तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से की थी। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान में 77 हजार 940 खेत तालाब, 1 लाख 3 हजार 900 डगवेल रिचार्ज और 992 अमृत सरोवर बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। इसे समय रहते पूरा कर लिया गया है। प्रदेश में 21 जून की स्थिति में 82 हजार 310 खेत तालाब, 1 हजार 283 अमृत सरोवर और 1 लाख 3 हजार कुओं में रिजार्च पिट (डगवेल रिचार्ज विधि) बनाने का काम चल रहा है। इसके अलावा 19 हजार 949 पुराने कार्य भी पूरे किए गए हैं। जबकि, जल गंगा संवर्धन अभियान को पूरा होने में एक सप्ताह का समय शेष है। यह सभी कार्य मनरेगा योजना से कराए जा रहे हैं, जिसमें 2334 करोड़ रुपये खर्च की जा रही है।

2 लाख 30 हजार से अधिक जल दूतों ने कराया पंजीयन

प्रदेश में जल संरक्षण के प्रति अधिक से अधिक लोग जागरूक हों, इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा 1 लाख 62 हजार 400 जल दूत बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यह लक्ष्य भी निर्धारित लक्ष्य से अधिक हो गया है। प्रदेश में अब तक 2 लाख 30 हजार से अधिक जलदूतों ने पंजीयन कराया है। प्रदेश में पहली बार खेत तालाब, अमृत सरोवर और डगवेल रिचार्ज बनाने में सिपरी साफ्टवेयर, एआई और प्लानर सॉफ्टवेयर जैसी तकनीक का उपयोग किया गया है, जिससे निर्धारित लक्ष्य को समय रहते प्राप्त करने में आसानी हुई है। साथ ही गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। अब यह तकनीक देश के दूसरे राज्यों के लिए एक मॉडल रूप में विकसित हो रही है। अभियान की प्रगति के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को नियमित रूप से जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए डैशबोर्ड डाटा को ढ्ढ के माध्यम से विश्लेषित कर सीधे संबंधित अधिकारियों को वाट्सऐप पर उपलब्ध कराई जा रही है। ढ्ढ रिपोर्ट में जिले की विशेषताओं को अभियान के लक्ष्य के साथ अन्य जिलों की प्रगति से तुलना करते हुये जिले की प्रगति को दिखाया जाता है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी से मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की मुलाकात

प्रदेश के विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों में शामिल होने का दिया आमंत्रण

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से भेंट कर प्रदेश में चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें मध्यप्रदेश में विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि-पूजन कार्यक्रमों के लिए मध्यप्रदेश आने के लिए आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि जल संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान्तर्गत खंडवा जिला भूगर्भ-जल भंडारण में पूरे देश में प्रथम आया है और मध्यप्रदेश ने शीर्ष चार राज्यों में स्थान बनाया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की प्रेरणा गुजरात सरकार से मिली है, जहाँ पुराने कुएं, बावड़ियों, नदी तटों का जीर्णोद्धार कर भूगर्भ-जल भंडारण के विशेष काम किये गये हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को अभियान के समापन कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से सम्मिलित होकर आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रण दिया, जिसे प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सहर्ष स्वीकार किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में चार स्तंभों-गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास की दिशा में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने, खाद्य प्र-संस्करण इकाइयों को बढ़ावा देने और कृषि आधारित उद्योगों के नए अवसर सृजिन करने के उद्देश्य से आगामी 12-13 और 14 अक्टूबर को सीहोर जिले में 2 लाख से अधिक किसानों का वृहद सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008